

रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एम० एम० 14/91.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 19 सितम्बर, 1991/28 भाद्रपद, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिमूचना

दिनांक 3 जुलाई, 1991

सं० एल० एल० आर० (राजभाषा) (बी) (16)-4/91.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश गुड कण्डक्ट प्रिजनर्ज प्रोबेशनल रिलीज ऐक्ट, 1968 (1968 का 22)” के संलग्न

अधिप्रमाणित राजभाषा रुपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसका परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परीबीक्षात्मक रिहाई अधिनियम, 1968

(1968 का 22)

(31-5-1991 को यथा विद्यमान)

राज्य सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों पर, सदाचरण बंदियों की रिहाई का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सदाचरण बंदी परीबीक्षात्मक रिहाई अधिनियम, 1968 है । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं ।

(क) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ; और

(ख) "अधिसूचना" से राजपत्र हिमाचल प्रदेश में उचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ।

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 401 में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति कारावास के दण्डादेश के अधीन, कारागार में रखा गया है, और सरकार को उसके पूर्ववृत्त या उमके कारागार में आचरण से यह प्रतीत हो कि सम्भाव्यतः वह अपराध नहीं करेगा और उपयोगी तथा परिश्रमी जीवन बिताएगा, यदि उसे कारागार से रिहा कर दिया जाए तो, सरकार उसका अनुज्ञप्ति द्वारा इस शर्त पर रिहा करने की अनुज्ञा दे सकेगी कि उसको सरकारी अधिकारी या धर्मनिरपेक्ष संस्था अथवा बंदी के धर्म को मानने वाली किसी व्यक्ति या सोसाइटी के जिसका नाम अनुज्ञप्ति में लिखित है और जो उसे अपनी सुपुर्दगी में लेने के लिए राजामन्द है, पर्यवेक्षण या प्राधिकार के अधीन रखा जाए ।

सरकार को; अपने द्वारा अधिरोपित शर्तों पर, अनुज्ञप्ति द्वारा रिहाई की शक्ति ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में अभिव्यक्ति 'कारावास का दण्डादेश' के अन्तर्गत, जमाने के संदाय के व्यक्तिक्रम में कारावास और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) के अध्याय 8 के अधीन प्रतिभूति देन में अमफल रहने के लिए कारावास, भी है ।

4. धारा 3 के उपबन्धों के अधीन की गई अनुज्ञप्ति उस तारीख तक प्रवृत्त रहेगी जब तक रिहा किया गया व्यक्ति, यदि वह अनुज्ञप्ति पर रिहा न किया गया होता, उसका कारावास प्राधिकृत करने वाले आदेश या वारण्ट के निष्पादन में कारागार से उन्मुक्त किया जाता, अथवा जब तक अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत नहीं किया जाता, इनमें से जो भी पहले हो ।

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रवृत्त रहेगी ।

5. वह कालावधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति पर जो प्रवर्तन में है, अनुपस्थित रहता है, कारावास की अवधि को संगणना के

विष्ट अवधि को संगणना

में, रिहाई की अवधि का, कारावास के रूप में संगणित किया जाना।

प्रयोजन के लिए और उसके कारावास को माफ करने की माता की संगणना के प्रयोजन के लिए, जो उसे ऐसे माफ करने से सम्बद्ध प्रवृत्त किन्हीं नियमों के अधीन अधिनिर्णित की जाए, उस कारावास की अवधि का भाग मानी जाएगी, जिसके लिए उसे दण्डादिष्ट किया गया था।

अनुज्ञप्ति का प्ररूप। 6. धारा 3 के उपबन्धों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी शर्तें होंगी जो सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अथवा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे।

अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत करने की शक्ति। 7. (1) सरकार, धारा 3 के उपबन्धों के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति को, किसी भी समय प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन पारित प्रतिसंहरण आदेश में, वह तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसकी अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन समाप्त हो जाएगा, और उस व्यक्ति पर उसकी तामील जिसकी अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की गई है, ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी सरकार नियमों द्वारा विहित करे।

(3) सरकारी अधिकारी, जिसके प्राधिकार या पर्यवेक्षण के अधीन बन्दी को अधिनियम की धारा 3 के अधीन रिहा किया गया था, जब तक अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का आदेश पारित नहीं किया जाता, उसे ऐसे स्थान पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी सरकार द्वारा विहित की जाए, गिरफ्तार करने और निरुद्ध रखने का आदेश कर सकेगा।

रिहा फरार व्यक्तिओं का जो पर्यवेक्षण से निकल भागते हैं दण्डनीय होना। 8. (1) यदि कोई व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या धर्म निरपेक्ष संस्थान अथवा सोसाइटी या उस व्यक्ति के पर्यवेक्षण या प्राधिकार से जिसकी सुपुर्दगी में उसे धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रखा गया है, निकल भागता है या यदि कोई व्यक्ति, जिसकी विधिपूर्ण हेतुक के बिना, जिसको साबित करने का भार उस पर होगा, उस कारागार में, जिससे वह रिहा किया गया था, प्रतिसंहरण आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व वापस आने में असफल रहता है तो, ऐसा व्यक्ति मैजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अर्थ के अन्तर्गत, संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति। 9. (1) सरकार, अधिमूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम में संगत नियम बना सकेगी ; —

- (क) अनुज्ञप्ति का प्ररूप और शर्तें जिन पर बन्दी रिहा किया जा सकेगा ;
- (ख) उन सरकारी अधिकारियों, सोसाइटियों या व्यक्तियों की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करने, जिसके प्राधिकार या पर्यवेक्षण के अधीन सशर्त रिहा बन्दी को रखा जा सके ;
- (ग) उन अपराधियों के वर्गों को, जो सशर्त रिहा किए जा सकेंगे, और कारावास की अवधि जिसके पश्चात् वे इस प्रकार रिहा किए जा सकेंगे, परिनिश्चित करने के लिए ;
- (घ) साधारणता इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र में जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या उपर्युक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है तो तत्पश्चात् वह उस परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. मदाचरण बंदी परीक्षात्मकता रिहाई अधिनियम, 1926 (1926 का 10) जो हिमाचल प्रदेश (विधियों की प्रयोज्यता) आदेश, 1948 द्वारा हिमाचल प्रदेश में लागू किया था और जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल में जोड़े गए क्षेत्रों में भी प्रवृत्त था, का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

निरसन और
व्यावृत्ति।

परन्तु एतद्द्वारा निरसित अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचना या प्रारम्भ अथवा जारी की गई कार्यवाहियां भी हैं, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएंगी।

शिमला-2, 3 जुलाई, 1991

सं० एल० आर० (राजभाषा) बी (16)-3/91.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनूपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “दि हिमाचल प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ स्मॉकिंग (जो हाउसेज) ऐक्ट, 1968 (1969 का 4)” के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध (प्रदर्शन गृह) अधिनियम, 1968

(1969 का 4)

(30-4-91 को यथा विद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन गृहों में धूम्रपान प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश धूम्रपान प्रतिषेध (प्रदर्शन गृह) अधिनियम, 1968 है ।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।
 - (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हों ;—
- (क) “श्रोताकक्ष” से प्रदर्शन गृहों का वह भाग अभिप्रेत है जहाँ मनोरंजन, चल चित्रिकी प्रदर्शन, नृत्य, नाट्य प्रदर्शन या किसी आमोद को देखने के लिए जनता को स्थान उपलब्ध कराया जाता है ;
 - (ख) “अधिसूचना” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में उचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;
 - (ग) “प्रतिषिद्ध अवधि” में प्रदर्शन गृह में मनोरंजन प्रारम्भ होने से तीस मिनट पूर्व से मनोरंजन समाप्त होने तक की अवधि, अभिप्रेत है ;
 - (घ) “प्रदर्शन गृह” से ऐसी कोई इमारत या अन्य बन्द और छत वाला स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता के सदस्यों को, चाहे संदाय पर या अन्यथा, किसी मनोरंजन, चलचित्रिकी, प्रदर्शन, नृत्य अथवा नाट्य प्रदर्शन या अन्य प्रकार के किसी आमोद को देखने के लिए प्रवेश दिया जाता है ;
 - (ङ) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ; और
 - (च) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।

3. कोई भी व्यक्ति, प्रतिषिद्ध अवधि के दौरान, श्रोताकक्ष में धूम्रपान नहीं करेगा ।

श्रोताकक्ष में धूम्रपान क प्रतिषेध ।

4. (1) प्रदर्शन गृह में निर्देशन या प्रदर्शनी के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, प्रमुख रूप से नोटिस चिपका कर और किसी चलचित्रिकी प्रदर्शनी की दशा में भी, स्लाइडें प्रदर्शित करके दर्शकों के ध्यान में यह बात लाएगा कि श्रोताकक्ष में प्रतिषिद्ध अवधि के दौरान धूम्रपान करने वाला कोई व्यक्ति बाहर निकाले जाने और अभियोजन के लिए दायी होगा ।

नोटिस चिपकाने और स्लाइडों को प्रदर्शित करने का प्रबन्ध ।

(2) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए पचास रुपये तक और द्वितीय या पश्चात्तुर्वर्ती अपराध के लिए दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

श्रोताकक्ष में धूम्रपान के लिए दण्ड। 5. (1) कोई मैजिस्ट्रेट या कोई भी पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेषतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपना समाधान करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, श्रोताकक्ष में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को जो श्रोताकक्ष में प्रतिषिद्ध अवधि के दौरान धूम्रपान करते हुए पाया जाता है, और जो, —

- (i) जब ऐसे मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा धूम्रपान न करने का निदेश देने पर धूम्रपान करना नहीं छोड़ता है; या
- (ii) मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर, अपना नाम व पता तुरन्त घोषित करने से इन्कार करता है या असफल रहता है; या
- (iii) मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अथवा ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में मिथ्या नाम और पता देने का युक्तियुक्त रूप से सन्देह पाया जाता है;

को संधिप्त श्रोताकक्ष से बाहर निकाल सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति, इस तरह बाहर निकाले जाने का विरोध करता है तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अथवा ऐसा प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए पच्चीस रुपये तक और द्वितीय या पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

बाहर किया गया व्यक्ति के प्रवेश के लिए किए गए किसी संदाय के प्रतिदाय या किसी अन्य प्रतिकर के लिए हकदार नहीं होगा।
हकदार नहीं।

नियम बनाने की शक्ति। 7. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमाम्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां। 8. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से, —

- (क) प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व, हिमाचल प्रदेश संघ क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्रों में विस्तारित दि बिहार प्रोहिबिशन आफ स्मोकिंग (शो हाउसेज) ऐक्ट, 1954 (1954 का 10); और

(ख) पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तर्गत क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त दि पंजाब प्रोहिबिशन आफ् स्मोकिंग (मिनेमा एण्ड थियेटर हालज़) ऐक्ट, 1951 (1951 का 8) ;

निरमित हो जाएंगे :

परन्तु उक्त अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

शिमला-2, 3 जुलाई, 1991

सं० एल० एल० आर० (राजभाषा) बी (16)-5/91---हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश फूट नर्सरीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1973 (1973 का 13)" के संलग्न अधिप्रमाणित राजभाषा रूपान्तर कोणतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश फल पोषणाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 15) को यथाविद्यमान

हिमाचल प्रदेश में फल पोषणालाओं के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश फल पोषणाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह ऐसा तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

संक्षिप्त
नाम, प्रसार
और
प्रारम्भ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, —

परिभाषाएं।

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "निदेशक" से निदेशक बागवानी, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(ग) "निरीक्षण अधिकारी" से निदेशक बागवानी द्वारा पोषणाला निरीक्षण के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो बागवानी निरीक्षक या पोष संरक्षण निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "पोषणाला पोषक" से फल के पौधों के उत्पादन और बिक्री के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "राजपत्र" से राजपत्र हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(छ) "पौध सामग्री" से पौधा उगाने के लिए प्रयुक्त कोई प्रजनन सामग्री अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत कली, प्ररोह, प्रकंद, बीज और कलम करना भी है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "प्रकंद" से फल पौधा या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जिस पर किसी फल पौधे की कलम या कलिका की गई हो ;

(ञ) "सांक्रुक" या "कलिकायुक्त टहनी" से पौधे का वह भाग अभिप्रेत है जो प्रकंद या वृक्ष की कलम या कलिक लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ट) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

3. कोई भी पोषणाला पोषक, जिसकी अपनी पोषणाला है, और उसके कब्जे में है, सक्षम प्राधिकारी के पास अपने आपको या अपनी फर्म को रजिस्ट्रीकृत कराए बिना और विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना पोषणाला पौधों या पौधा सामग्री का उत्पादन और विक्रय नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकरण
और
अनुज्ञप्ति।

टिप्पणी:—जहाँ पोषणाला पोषक के पास भिन्न-भिन्न नगरों और गांव में एक से ज्यादा फल पौधालाएँ हैं तो उसे प्रत्येक ऐसी फल पौधाला के लिए अलग अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी पड़ेगी।

अनुज्ञप्ति के लिए 4. (1) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा और यह विहित प्ररूप में होगा।

आवेदन-पत्र (2) ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, यदि सक्षम और मंजूरी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि —

तथा

इन्कार।

(क) फल पौधशाला, फल पौधों के उचित प्रजनन के लिए जिसके बारे में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया है, उपयुक्त है ;

(ख) आवेदक ऐसी किसी पौधशाला को चलाने या स्थापित करने के लिए सक्षम है ;

(ग) वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिसूचित अन्य शर्तों को पूरा करता है ; और

(घ) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के लिए विहित फीस संदत्त कर दी है और विहित प्रतिभूति, यदि कोई हो, भी दे दी है ; तो ऐसा प्राधिकारी आवेदक को अनुज्ञप्ति की शर्तों और इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन नियमों के अनुसार फल पौधशाला चलाने या स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति इसके जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी और इसका समय-समय पर ऐसी फीस के संदाय, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के पूरा करने पर, जैसी कि विहित की जाए, नवीकरण किया जा सकेगा।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार करता है तो वह ऐसे इन्कार के कारणों को लेखबद्ध करेगा और अपने आदेश की प्रति आवेदक को संसूचित करेगा।

अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्द किया जाना।

5. सक्षम प्राधिकारी धारा 4 के अधीन किसी मंजूर या नवीकृत अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित कारणों से निलम्बित या रद्द कर सकेगा —

(क) यदि अनुज्ञप्तिधारी ने दिवालिया न्यायनिर्णीत करने के लिए आवेदन किया है या न्यायनिर्णीत दिवालिया कर दिया गया है ; या

(ख) यदि वह पूर्णतः या भागतः फल पौधशाला के नियंत्रण से अलग हो गया है ; या

(ग) यदि उसने ऐसी फल पौधशाला चलाना या उसका कब्जा समाप्त कर दिया है ; या

(घ) यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में वह ऐसी फल पौधशाला को चलाने या रखने में अक्षम हो गया है ; या

(ङ) यदि उसने अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तदधीन नियमों का उल्लंघन किया है या उनका अनुपालन करने में असफल रहा है ; या

(च) यदि उसने सक्षम प्राधिकारी या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को अपनी अनुज्ञप्ति या उस अधिनियम या तदधीन नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रिकार्ड को अभ्यर्पित या पेश करने से इन्कार किया हो ; या

(छ) किसी अन्य विहित आधार पर।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी को उन आधारों को सूचित करेगा जिन पर कार्रवाई करना प्रस्तावित है और उसे इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन उसके सम्बन्ध में रद्द आदेश के पारित न किए जाने तक, अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर सकेगा।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अनुज्ञप्तिधारी को समूचित की जाएगी।

6. अनुज्ञप्ति की समाप्ति या इसके निलम्बित अथवा रद्द किए जाने के आदेश की प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी को वापस करेगा।

अनुज्ञप्ति का वापस करना।

परन्तु ऐसा प्राधिकारी ऐसी समाप्ति तक की निलम्बित या रद्द किए जाने के पश्चात् पौधशाला पोषक को अपनी फल पौधशाला बन्द करने के लिए समर्थ बनाने के लिए, ऐसा उचित अवसर प्रदान कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

7. यदि धारा 4 के अधीन मंजूर या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति गुम, नष्ट, विवृत या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो सक्षम प्राधिकारी, आवेदन करने और विहित फीस के संदाय पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा।

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी करना।

8. (1) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत करने में इन्कार करने वाले सक्षम अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रेषण और गीति से, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो विहित किया जाए :—

अपील।

परन्तु यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो अपील प्राधिकारी विहित अवधि के पश्चात् भी, अपील ग्रहण कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी का सुनने के पश्चात् अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन पारित कोई आदेश, धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

9. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी समय ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मामले का रिकार्ड मंगा सकेगी और उसका निरीक्षण कर सकेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि यह उचित समझे :

पुनरीक्षण।

परन्तु राज्य सरकार ऐसे आदेश के सम्बन्ध में जिसके विरुद्ध धारा 8 के अधीन की गई अपील लम्बित है या उसके लिए विहित अवधि के समाप्त होने से पूर्व अपील नहीं की गई है, इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी।

(2) इस धारा के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

10. (1) रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पोषक या पौधशाला पोषकों की फर्म, सांक्रुरक और प्रकन्द आदि के सम्बन्ध में प्रजनन के लिए ऐसी ही पौध सामग्री प्रयोग में लाएंगी, जिसकी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सिकांरिश की जाए।

पौध सामग्री का प्रजनन के लिए उपयोग किया जाना।

(2) रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पोषक या पौधशाला पोषकों की फर्म अच्छी वंशावली के सन्तति वृक्ष रखेगी और उनकी संख्या पञ्चीस वृक्षों की न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रजनित पौधों को न्यायोचित ठहराएंगी।

अभिलेख
और इसका
निरीक्षण।

11. रजिस्ट्रीकृत पौधशाला पोषक या पौधशाला पोषकों को प्रबन्ध, सांक्रुष्य, अंकुर के उद्गम स्त्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगी और मांगने पर निदेशक या किसी निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के लिए पेश करेगी।

प्लाटों और
पेड़ों को
कीड़ों,
विनाशकीटों
और
बिमारियों
से रहित
रखा जाना।

12. पौधशाला प्लाट और पौधशाला पौधों और पेड़ों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए गए पौधों और पेड़ों की भी ऐसे कीड़ों, विनाशकीटों और बीमारियों से रहित रखा जाएगा जो विहित की जाएं।

पौधशालाओं
का
निरीक्षण।

13. (1) निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि पौधशाला के पौधों और पेड़ों को उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए गए पौधशाला प्लाट और पौधे, कीड़ों, विनाशकीटों और बिमारियों से रहित रखे गए हैं समय-समय पर पौधशालाओं का निरीक्षण कर सकेगा और पौधशाला पोषकों को संक्रमित या ग्रस्त पौधों या पेड़ों को विहित अवधि के भीतर हटाने और नष्ट करने के लिए निदेश दे सकेगा।

(2) पौधशाला पोषक लिखित रूप में निदेश प्राप्त करने पर ऐसे पौधों या पेड़ों को विहित अवधि के भीतर हटाएगा या नष्ट करेगा, ऐसा करने में असफल रहने पर निरीक्षण अधिकारी उन्हें पौधशाला पोषक के खर्च पर हटवाएगा या नष्ट करवाएगा और उस द्वारा ऐसा करने में उपगत व्यय पौधशाला पोषक से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

पैकेज और
उस पर
लेबल
लگانा।

14. (1) ऐसे पैकेज या पात्र पर जिसमें पौधा या पौधे रखे गए हों, बेची गई किस्म और प्रकार को निर्दिष्ट करने के लिए, सुनिश्चित रूप से लेबल लगाया जाएगा।

(2) यदि पैकेज या पात्र में एक से अधिक किस्म और प्रकार के पौधे हों तो प्रत्येक पौधे को लेबल लगाया जाएगा।

(3) लेबल पर प्रबन्ध और सांक्रुष्य का नाम लिखा जाएगा।

रजिस्टर
रखना।

15. (1) प्रत्येक पौधशाला पोषक विहित प्रारूप में रजिस्टर रखेगा जिसमें बेची गई पौध सामग्री और केसा के नाम और पूर्ण पते के बारे में पूर्ण सूचना अन्तर्विष्ट होगी।

(2) पौधशाला पोषक द्वारा रजिस्टर संव्यवहार की समाप्ति की तारीख से कम से कम दस वर्ष तक परिरक्षित रखा जाएगा।

विक्रय के
लिए प्रजनित
को जाने वाली
किस्में।

16. (1) विक्रय के लिए प्रजनित किस्में वही होंगी जिनकी बागवानी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा सिफारिश या अनुमोदन किया गया हो।

(2) यदि पौधशाला पोषक द्वारा कोई किस्म या किस्में निर्यात की गई हैं या अपनी सम्पदा पर विकसित की हैं या प्रजनन के लिए आशयित हैं तो ऐसी किस्मों को सुविन्न या अलग नाम से विक्रय करने से पूर्व, उनका पूरा विवरण निदेशक या निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत प्राधिकृत राज्यपत्रित अधिकारी को दिखाया जाएगा और उस द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

17. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्वन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, फल पौधों के जैसी यह अधिरोपित करे, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाषित शुल्क सीमा के पार से राज्य के अन्यथा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा घोषित किन्हीं अपरिचित वंशावली या किसी संक्रामक बीतर लाने अथवा सामाजिक बोझारी या या विनाशकरीट से प्रभावित फल पौधों के हिमाचल प्रदेश में या बाहर ले जाने को प्रति-विद्ध करने या विनियमित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

18. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या वनाए गए किन्हीं शास्तियों। नियमों का उल्लंघन करता है जिसका उल्लंघन इस धारा के अधीन दण्डनीय है अथवा ऐसे किसी उपबन्ध या नियम का उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है अथवा उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, तो वह कारावास से जिम्की अधधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि इस धारा के अधीन अपराध करने वाली कोई कम्पनी हो तो कम्पनी और अपराध करने के समय इसके कारोबार के संचालन के लिए कम्पनी के प्रतिउत्तरदायी प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति भी, अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को दण्डनीय नहीं बनाएगी जो यह साबित कर दें कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को निवारित करने के लिए हर प्रकार की सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(3) उप-धारा 2 में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया हो, और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मोनानुकूलता से किया गया है अथवा अपराध का किया जाना उनकी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और फर्म या व्यष्टियों का संगम इसके अन्तर्गत है ; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” फर्म में भागीदार है।

19. कोई भी न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद अपराधों इत्यादि का संज्ञान। के सिवाये, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

20. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड इस अधिनियम संहिता की धारा 21 (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

21. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए व्यक्तियों का संरक्षण। पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति। 22. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे—

- (क) इस अधिनियम द्वारा विहित करने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या स्वीकृत सभी मामलों ;
- (ख) पौधशाला पौधकों को मन्जूर किए जाने वाली अनुज्ञप्तियों में अन्तःस्थापित की जाने वाली शर्तें और ऐसे आवेदनों और अनुज्ञप्तियों का प्रारूप ;
- (ग) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के प्रयोग में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (घ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर, लेखा पुस्तकें और अभिलेख और उनके रखने की रीति और अवधि जिसके लिए वे रखे जाएंगे ;
- (ङ) ऐसी परिस्थितियाँ, जिनमें अनुज्ञप्तिधारियों से प्रतिभूति अपेक्षित होगी और उन द्वारा दी गई प्रतिभूति समपूत की जा सकेगी और रीति जिसमें ऐसे समपूरण के फलस्वरूप कोई भी देय राशि वसूल की जा सकेगी ;
- (च) फल पौधशालाओं का दक्षता पूर्वक संचालन, सुधार और विकास ;
- (छ) उन फल पौधों का पता लगाना, निरीक्षण करना, प्रमाणन, वहन या नष्ट करने का ढंग जिनके सम्बन्ध में धारा 17 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो या किसी अन्य वस्तु का जिसका इसके साथ सम्पर्क या सामीप्य हो और उन अधिकारियों की शक्तियों और कर्तव्यों का विनियमन जो इस सम्बन्ध में नियुक्त किए जाएं ;
- (झ) धारा 8 और 9 के अधीन अपील/पुनरीक्षण में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और उसकी परिसीमा ;
- (ञ) नाशकियों, बीमारियों और कीड़ों का विहित किया जाना जिनसे पौधशाला पौधों का बचाव किया जाना अपेक्षित है ;
- (ट) पौधशालाओं के निरीक्षण में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथा-शीघ्र, विधान सभा के समक्ष वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में हो या अधिक अनुक्रमवती सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन। 23. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का, मित्राये नियम बनाने की शक्ति के, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगी।

24. जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द किया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उसके लिए प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा न ही वह अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्द किए जाने के लिए कोई प्रतिकर नहीं।

25. हिमाचल प्रदेश में प्रथम नवम्बर, 1966 से पूर्व समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त, निरसन और व्यावृत्तियाँ।
हिमाचल प्रदेश फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 11) और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्र को यथा लागू, पंजाब फल पौधशाला रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1961 का 13) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु एतद्द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकृत पौधशाला, जारी की गई अधिसूचना, आदेश या निदेश, बनाए गए नियम, प्रारम्भ की गई या चालू कार्यवाहियाँ भी ह) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

